अप्रैल 2023

दीप कमल

श्रद्धांजलि...

स्व. भुनेश्वर साहू की श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, सांसद श्री सुनील सोनी समेत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ का हिन्दू समाज शामिल हुआ।

सरगुजा संभाग के पहाड़ी कोरवा परिवार के सामूहिक आत्महत्या के मामले में भाजपा जांच दल की रिपोर्ट पार्टी ने महामहिम राज्यपाल को सौंपी ।

भाजपा के संगठन जिला प्रभारियों की बैठक में शामिल श्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव, महामंत्री संगठन श्री पवन साय एवं विधायक श्री शिवरतन शर्मा। स्वागत करते हुए पूर्व सांसद श्री मधुसूदन यादव।

दीप कमल

वर्ष-19, अंक-4, अप्रैल 2023

संपादक
सुभाष राव

कार्यकारी संपादक
पंकज कुमार झा

मुद्रक एवं प्रकाशक अरुण साव द्वारा, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के लिए, मूणत ऑफसेट प्रिंटर्स से मुद्रित एवं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, बोरियाकला, रायपुर से प्रकाशित।

स्वत्वाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

ई-मेल
jay7feb@gmail.com

फोन
0771-2233500, 2233511

सोशल मीडिया से

Narendra Modi @nare... · 38m
India government official

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इन लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है! प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां काफी उत्साहित करने वाली हैं।

Arun Sao @ArunSao3 · 2d

"अब सड़क मेरे खेत तक जाती है", आनंदित जनाकरामजी ने अपने गांव पेंडरबेरा में सड़कों की कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए कहा। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों में रहने वाला भारत सड़क क्रांति का साक्षी बन रहा हैं। (1/5)

Show this thread

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

छत्तीसगढ़

➡ छत्तीसगढ़ के सूरजपुर और सरगुजा जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर अंबिकापुर रामानुजगंज गढ़वा रोड के अंबिकापुर बाईपास (संजयनगर से राजपुरी खुर्द गांव खंड तक) के पेव्ड शोल्डर के साथ 2-लेन मार्ग निर्माण को ईपीसी मोड के तहत 143.94 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है।

#PragatiKaHighway #GatiShakti @PMOIndia @bhupeshbaghel @drramansingh @renukasinghbjp @ArunSao3 @BJP4CGState

Translate Tweet

Dr Raman Singh @drramansingh

दाऊ @bhupeshbaghel के काले कुशासन में यह बड़ी गड़बड़ है कि भ्रष्टाचार तो फटाफट हो जाता है लेकिन जब चोरी पकड़ी जाती है तब कार्रवाई नहीं होती।

करोड़ों के चावल डकार कर अब कोई ठोस कदम तो यह शासन उठा नहीं पा रही फिर केंद्रीय एजेंसियां कदम उठाती हैं तो पूरी कांग्रेस विलाप में छाती पीटने लगती है।

Translate Tweet

100 करोड़ का चावल घोटाला, अब तक 24 लाख ही वसूले

BJP Chhattisgarh @BJP4CGState

विडंबना देखिए, जिस समय जिहादियों द्वारा बर्बरता से मारे गये हिन्दू युवक भुनेश्वर साहू की चिता जल रही थी, पूरा छत्तीसगढ़ ग़मगीन था, उसी समय मुख्यमंत्री भूपेश ईफ्तारी कर रहे थे।

#छत्तीसगढ़_बनता_जिहादगढ़ #Bemetara #BhuneshwarSahu

Translate Tweet

Ajay Chandrakar @Chandrakar_Ajay

मान. मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ (कांग्रेस शोषित) - जनाब शारीक खान को शायद आपने अच्छे उद्यमी का पुरस्कार दिया था... स्पा सेंटर या #भिलाई में #वेश्यालय (पुलिस के अनुसार)ही #कांग्रेस_सरकार की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ उद्यम है...? आपको दुर्ग पुलिस के ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए...

Translate Tweet

डबल इंजन सरकार यानी दोगुना कल्याण | डबल इंजन सरकार यानी दोगुना विकास

डबल इंजन सरकार यानी जेहादियों को तेजी से रौंदता हुआ बुलडोजर

हम सभी जानते हैं कि महान भारत राष्ट्र वास्तव में राज्यों का एक संघ भी है। भारतीय संविधान के अनुसार त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यहां संचालित है, जिनमें मुख्य रूप से राज्य और केंद्र के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। ऐसे में विकास की विचारधारा वाली पार्टी अगर दोनों स्थान पर सत्ता में रहे तो राजनीतिक दुराग्रह आदि के कारण विकास में किसी तरह का वैसा अवरोध नहीं हो पाता है जैसा फिलहाल छत्तीसगढ़ में हो रहा है।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 'डबल इंजन सरकार' के फायदे गिनाते हुए हमेशा कहते हैं कि इससे दोगुना कल्याण और दोगुना विकास होता है। केंद्र के साथ-साथ राज्यों में भी भाजपा की सरकार बने, इसके लिए 'डबल इंजन' की सरकार भाजपा का प्रमुख आह्वान है। प्रदेश के 17 राज्यों में भाजपा और राजग की सरकारें भी इसी विचारधारा के अनुरूप, मोदी जी द्वारा दिए मूलमंत्र 'सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' को अपनाकर लगातार कार्य कर रही है।

भारत में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 'डबल इंजन' की सरकार का आह्वान इसलिए और अधिक प्रासंगिक है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इससे पहले लम्बे समय तक गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य के सफलतम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जाहिर हैं उन्हें न केवल राज्यों के समक्ष उत्पन्न होती चुनौतियों की बेहतर समझ है, बल्कि एक प्रदेश को भी मॉडल के रूप में विकसित करने का वे अनुभव भी रखते हैं। उन्हें दोनों इंजन का चालक होने का प्रचुर अनुभव है। इसलिए उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले केंद्रीय करों में राज्यों का अंश सीधे 10 प्रतिशत बढ़ा दिया था। यानी 32 से 42 प्रतिशत। उन्होंने राज्यों के हिस्से में करीब 33 प्रतिशत राशि की वृद्धि कर दी थी। इसके अलावा वे बिना किसी भेदभाव के राज्यों के विकास में तत्पर रहते हैं, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो। लेकिन राजनीतिक द्वेष और विकास की विचारधारा से भिन्न विचार रखने के कारण अन्य दलों द्वारा शासित राज्यों में इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।

डबल इंजिन सरकार के बिना विकास किस तरह बाधित होता है, 'पीएम आवास योजना' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी जी ने स्वतंत्रता के अमृत काल में देश के हर परिवार को पक्के मकान का लक्ष्य सामने रखते हुए इस योजना की शुरुआत की। जहां देशभर में इस योजना से करोड़ों पक्के मकान बने वहां, वहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह योजना अमृत की तरह जीवनदायिनी साबित हुई है। लेकिन 'सिंगल इंजन' की सरकार होने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे लागू करने में लगातार अवरोध पैदा करते हुए 16 लाख से अधिक गरीबों के सिर से छत छीन ली। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस मामले में साफ कहना रहा कि चूंकि इस योजना में 'प्रधानमंत्री' शब्द जुड़ा है, इस कारण वे राज्यांश नहीं देंगे। यहां तक कि इस दुराग्रह का विरोध करते हुए कांग्रेस के ही विभागीय मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया लेकिन बघेल सरकार के कारण यहां गरीब अपने आवास से वंचित हैं।

इसी तरह मोदी जी का 'अमृत काल' लक्ष्य सभी घरों तक नल से साफ़ पानी पहुँचाने का है। इस योजना में भी अभी तक 11 करोड़ से अधिक घरों तक स्वच्छ जल पहुंचा है लेकिन छत्तीसगढ़ का इंजन चूंकि कांग्रेस के चंगुल में है, तो प्रदेश आज इस योजना में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। आयुष्मान योजना,

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें 5 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला भूपेश सरकार ने किया है, आदि इसके दर्जनों उदाहरण हैं जहां कांग्रेस की जर्जर इंजन वाली सरकार ने घपले-घोटाले कर विकास की गाड़ी को पटरी से उतार दिया है। जहां मोदी जी की चावल योजना में भूपेश सरकार ने 5 हजार करोड़ से अधिक का गबन कर लिया, वहीं आयुष्मान योजना के बावजूद प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के 25 हजार से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए। अगर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आयुष्मान योजना की तो शुरुआत ही मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के ही जांगला से की थी, लेकिन ऐसे हर मामले में लगातार रोड़े अटकाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है।

इसी तरह डबल इंजन सरकार से कैसे शान्ति और व्यवस्था कायम होती है, वह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में देखा जा सकता है। देश भर से सबसे अधिक आतंक और गुंडों की बादशाहत के लिए बदनाम रहा उत्तरप्रदेश आज भाजपा की डबल इंजन सरकार में शान्ति-व्यस्था का उदाहरण बना हुआ है। जिस तरह गुंडों से निपटते हुए, आतंकियों को उनकी जगह दिखाते हुए, अतिक्रमणकारियों के नाजायज कब्जों पर बुलडोजर चलाते हुए 'योगी एक्सप्रेस' रफ़्तार से फर्राटा मार रही है, वह निस्संदेह छत्तीसगढ़ के लिए भी अनुकरणीय होगा।

छत्तीसगढ़ देश भर में शान्ति का टापू रहा है। यहां के अच्छे और सच्चे लोगों ने इससे पहले कभी कर्फ्यू और दंगों आदि का सामना नहीं किया था। प्रदेश निर्माण से लेकर कांग्रेस के कुछ कालखंड को छोड़ दें तो यहां के शासन की संवेदनशीलता, यहां की भलमनसाहत चर्चा का विषय रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से विकास की गाड़ी यहां एक चार्जशीटेड मुख्यमंत्री की रहनुमाई में सड़क से पलटी, लोगों ने भी पता नहीं किस खीज में जेहादियों तक को चुन कर 'रामराज्य' वाले क्षेत्र से भी सबसे अधिक बहुमत से सदन भेज दिया था, और परिणाम शीघ्र सामने आने लगे थे। कर्फ्यू, साम्प्रदायिक दंगे, मतान्तरण, अवैध घुसपैठ, गुंडागर्दी, लव जेहाद ... आदि चीजें बहुतायत में इसलिए होने लगी क्योंकि जनता ने कांग्रेस कोई वोट देकर डबल इंजन का एक इंजन फेल कर दिया था। ऐसे में हलाकान जनता अब शान्ति-सौहार्द्र का उत्तर योगी जी के प्रदेश में तलाश रही है। ऐसे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव का यह कहना वास्तव में आश्वस्ति देतासा नजर आया है कि भाजपा की सरकार बनने पर यहां भी डबल इंजन के साथ बुलडोजर चलाया जाएगा, जेहादियों-अपराधियों की बनती जा रही अवैध जागीरों पर। फिर प्रदेश के किसी भी परिवार का कोई भुनेश्वर साहू जैसा लाल किसी जेहादी के चंगुल में नहीं फंसेगा, फिर यहां के किसी अतीक-अशरफ या गुड्डू मुस्लिम का साहस नहीं होगा छत्तीसगढ़ की तरफ आँख उठा कर भी देख लेने की। फिर कोई पास्टर या गाजी हमें हमारी ही जमीन से बेदखल करने के लिए शासकीय परवाना लिए खड़ा दिखने की हिम्मत नहीं कर पायेगा।

न केवल क़ानून-व्यस्था बल्कि स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा समेत सभी संकेतकों में छत्तीसगढ़ अगर आज अनेक प्रतिष्ठित सर्वेक्षणों में सबसे नीचे किसी स्थान पर है, तो महज़ इसलिए क्योंकि यहां डबल इंजिन की सरकार नहीं है। जाहिर है कि पूर्वाग्रहग्रस्त कांग्रेस की रुचि केवल विभाजनकारी राजनीति को प्रश्रय देने की है। अतः भाजपा का यह मानना उचित ही है कि है कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार डबल इंजिन की सरकार बन जाने के बाद प्रदेश भी पूर्ववत गरीब कल्याण के राजमार्ग पर तेज़ी से अग्रसर होगा। फिर से छत्तीसगढ़ अपने पुरा वैभव की पुनर्स्थापना हेतु स्वयं को आत्मार्पित करेगा। ●●●

अपनी प्रतिक्रिया कृपया इस आईडी पर दें-

jay7feb@gmail.com

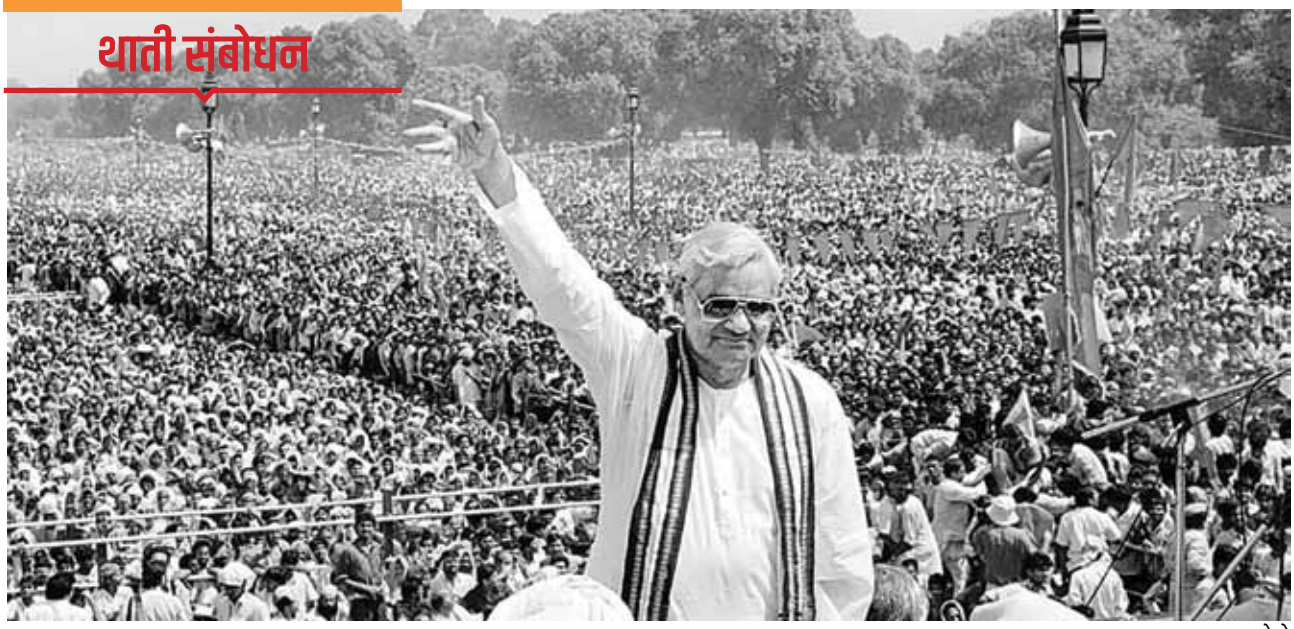

फाइल फोटो

अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा

-अटल बिहारी वाजपेयी

स्वागताध्यक्ष जी, प्रतिनिधि बंधुओं, बहनों और मित्रों, आज हम यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए एकत्र हुए हैं। मुझे निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित कर आपने मेरे प्रति जो स्नेह और विश्वास प्रकट किया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। मैं जानता हूं कि इस नाजुक घड़ी में किसी राजनीतिक दल का नेतृत्व ग्रहण करना कितना टेढ़ा काम है। मैं यह भी जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद अलंकार की वस्तु नहीं है। वस्तुतः यह पद नहीं, दायित्व है; प्रतिष्ठा नहीं, परीक्षा है; अधिकार नहीं, अवसर है; सत्कार नहीं, चुनौती है। परमात्मा से प्रार्थना है कि वह मुझे शक्ति तथा विवेक दे, जिससे मैं इस दायित्व को ठीक तरह से निभा सकूं।

नई पार्टी क्यों?

भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, इसके ब्यौरे में मैं नहीं जाना चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हम जनता पार्टी से खुशी से अलग नहीं हुए। आरंभ से अंत तक हम निरंतर इसी दिशा में प्रयत्नशील रहे कि पार्टी की एकता बनी रहे। हमें वह शपथ याद थी, जो हमने पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए राजघाट पर लोकनायक जयप्रकाश जी के समक्ष ली। परंतु दोहरी सदस्यता को समस्या बनाकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की गई कि जनता पार्टी से अलग होने के अतिरिक्त कोई और सम्मानपूर्ण विकल्प हमारे सामने नहीं रह गया।

जिन्होंने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की, उनके इरादे क्या थे, आज इसमें जाने से कोई लाभ नहीं होगा। परंतु यह उल्लेखनीय है कि दोहरी सदस्यता के प्रश्न को एक बहाना माननेवालों में ऐसे बहुत-से लोग थे, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी भी और किसी भी रूप में संबंध नहीं रहा। उनमें से अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के निर्माताओं में से हैं।

भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर विशेष

पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता

9 महीनों के अल्प समय में ही भारतीय जनता पार्टी को समूचे देश में जो व्यापक तथा प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ है, उससे हमारे अलग दल बनाने के निर्णय की पुष्टि ही हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 लाख से ऊपर है। इनमें से बहुत-से ऐसे हैं, जो पुराने जनसंघ में नहीं थे। फिर भी हमारे कुछ विरोधी, जिनमें प्रधानमंत्री अग्रणी हैं, यह कहते नहीं थकते कि भारतीय जनता पार्टी पुराने जनसंघ का ही नया नाम है। देश के सभी भागों तथा समाज के सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से परेशान और भविष्य में पार्टी की भारी संभावनाओं से भय खाकर ही ये लोग सच्चाई पर परदा डालने में लगे हैं।

अधूरे स्वप्न को साकार करने का प्रयास

लोकनायक जयप्रकाश के आह्वान पर बनी जनता पार्टी टूट गई। मगर लोकनायक ने इस महान् भारत देश के जिस रूप का स्वप्न देखा था, उसे हम नहीं टूटने देंगे। उनका स्वप्न, उनकी साधना, उनका संघर्ष, कुछ जीवन-मूल्यों में उनकी अडिग आस्था हमारी अनमोल विरासत के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकनायक जयप्रकाश के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए कृतसंकल्पित है।

मूल्याधिष्ठित राजनीति

आज हमारा देश बहुआयामी संकट के बीच गुजर रहा है। निरंतर बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति; दैनिक खपत की

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में कठिनाई, सांप्रदायिक दंगों की उग्रता तथा अवधि में वृद्धि; अधिकाधिक सामाजिक तनाव तथा हिंसा; हरिजनों, गिरिजनों, स्त्रियों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ता अत्याचार, पूर्वांचल की विस्फोटक परिस्थिति; ये इस संकट के कुछ आयाम हैं।

नैतिक संकट

इन समस्याओं का सामना करने का दायित्व जिन पर है, वे सत्ता की शतरंज पर मोहरे बैठाने में लगे हैं तथा इनका समाधान करने में असमर्थ हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि मूलतः हमारा संकट एक नैतिक संकट है। हमारे सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि नैतिक मूल्यों का स्थान स्वार्थसिद्धि एवं स्वार्थसिद्धि के साधन के रूप में सत्ता प्राप्ति ने ले लिया है।

सार्वजनिक जीवन में पतनावस्था

1969 में राष्ट्रपति पद के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार, जिनका नामांकन-पत्र स्वयं प्रधानमंत्री ने दाखिल किया था, को हराने के लिए अपनाए गए अनैतिक तरीकों से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह समय बीतने के साथ अधिकाधिक व्यापक और बलवती होती गई। 1975 में घोषित आपातस्थिति किसी अंतरबाह्य संकट का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बने रहने के लिए ही थी। जनता शासन में न्यायालयों में उपद्रव, विमान का अपहरण आदि गंभीर अपराधों को प्रोत्साहन देना, डराने-धमकाने के अन्य तरीके अपनाना, बड़े पैमाने पर दलबदल कराने की साजिश इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। 1980 के चुनाव में असामाजिक तत्त्वों का खुला उपयोग तथा थोक वोट प्राप्त करने के लिए सांप्रदायिक, जातीय तथा क्षेत्रीय भावनाओं को उकसाने के प्रयत्नों को भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है।

दोहरा मानदंड

नैतिकता का दोहरा मानदंड इसी प्रक्रिया का एक पक्ष है; जो सत्ता में है या सत्ताधारियों के कृपापात्र हैं, उनके निकट हैं, उनके संबंधी हैं, उनके लिए एक मानदंड तथा औरों के लिए दूसरा मानदंड। जनता शासन से पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने कृपा पात्रों और संबंधियों के विरुद्ध लगाए गए अभियोगों को, संथानम कमेटी की सिफारिशों की परवाह न करते हुए न्यायिक विचार के बिना अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत जनता शासन में प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने संबंधियों का मामला न्यायिक विचार के लिए भेजा। वास्तव में जनता शासन के 28 महीनों में ही इस प्रक्रिया की रोकथाम की दिशा में कुछ करने का प्रयत्न किया गया।

इस प्रकार की प्रक्रिया केवल शासक वर्ग तथा राजनीतिक दलों को प्रभावित करके नहीं जाती। वह समूचे समाज, नौकरशाही, उद्योगपतियों, व्यापारियों, यहां तक कि आम लोगों को भी अपने चंगुल में लपेट लेती है। स्वार्थसिद्धि तथा जैसे भी हो, अपना काम बना लेने की हवा चल पड़ती है। परिणामतः राष्ट्र की नैतिक शक्ति का ह्रास हो जाता है और राष्ट्र संकटों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता खो बैठता है।

नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना

वर्तमान संकट पर विजय पाने की पहली शर्त यह है कि हमारा सार्वजनिक जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। हमें इन मूल्यों को ढूंढ़ने के लिए देश के बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भारत के जन-जीवन की परंपरा में ही इन मूल्यों की जड़ें विद्यमान हैं। संप्रदाय, धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्र की सीमाओं से ऊपर उठकर आम भारतीयों का जीवन जिन मूल्यों से जुड़ा हुआ रहा है, जैसे— सहिष्णुता, सादगी, संतोष, परिश्रम, भाईचारे की भावना, उन्हीं को आधार बनाकर हमें नए समाज की रचना करनी है। आधुनिक परिस्थितियों के संदर्भ में जनजीवन का पुराना रूप बदलना वांछनीय है। पंडित नेहरू ने विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के उपयोग पर बल देकर विकास की जो दिशा दिखाई, उससे राष्ट्र की समृद्धि बढ़ी, किंतु वह समृद्धि कुछ लोगों तक ही सीमित रह गई। विषमता में वृद्धि हुई तथा अमीर और गरीब के बीच की खाई और अधिक चौड़ी हो गई। इस विकृति को दूर करने हेतु भारतीय परंपरा के मूल्यों को आधार बनाकर आगे चलना है और व्यक्ति को, विशेषकर दुर्बलतम व्यक्ति को, विकास प्रक्रिया का केंद्रबिंदु बनाना है। गांधी, जयप्रकाश तथा दीनदयाल प्रभृति मनीषियों ने प्रगति के इसी रूप का प्रतिपादन किया था। इसी दृष्टिकोण से जनता शासन में 'अंत्योदय', काम के बदले अनाज आदि योजनाएं हाथ में ली गई थीं।

इस प्रकार के समाज का निर्माण, जो शोषण तथा भेदभाव से रहित तथा कुछ जीवन मूल्यों पर आधारित हो, केवल बड़ी-बड़ी बातें करने तथा महात्मा गांधी का नाम रटने से नहीं हो सकता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। गरीब, किसानों, श्रमिकों, हरिजनों, गिरिजनों तथा अन्य शोषित वर्गों को संगठित करना होगा। इनकी संगठित शक्ति द्वारा ही इस प्रकार के समाज का निर्माण हो सकेगा। महात्मा गांधी ने जनशक्ति को जगाकर तथा संगठित करके ही विदेशी सरकार के विरुद्ध सफल संघर्ष किया था।

सिद्धांत आधारित राजनीति

हम जनता को तभी संगठित कर सकेंगे, हमारी बात वह तभी सुनेगी, जब हम उसके मन में अपनी विश्वसनीयता स्थापित कर सकें, उसे हम यह विश्वास दिला सकें कि हमारा उद्देश्य केवल स्वार्थसिद्धि और सत्ता हथियाना नहीं है, हमारी राजनीति कुछ मूल्यों, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है।

गांधीवादी समाजवाद

भारतीय जनता पार्टी ने सोच-समझकर गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार किया है। स्वयं गांधी जी अपने विचारों को किसी वाद का रूप देने के पक्ष में नहीं थे, किंतु उन्होंने जीवन को न केवल उसकी समग्रता में देखा था, बल्कि आधुनिक समस्याओं के हल के बारे में एक समन्वित दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया था।

उन्होंने मनुष्य का विचार मात्र आर्थिक इकाई के रूप में नहीं किया। सभी प्राचीन मनीषियों की भांति महात्मा जी भी मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक-दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति को अपना लक्ष्य बताते हैं। गांधी जी से पहले स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक समाजवाद की बात कही थी। गीता में साम्ययोग की चर्चा है। ईशावास्य उपनिषद् में किसी दूसरे के धन को ललचाई आंखों से न देखने का निर्देश एक ऐसी समाज रचना की ओर संकेत करता है, जो 'अपरिग्रह' पर आधारित होगी। 'सबै भूमि गोपाल की' के पीछे भी यही भावना है। यज्ञ में हर आहुति के बाद 'इदन्नमम्' (यह मेरा नहीं है) का उच्चारण व्यक्ति के मन पर यह छाप छोड़ने के लिए ही किया जाता है कि आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना चाहिए। ●●●

(मुंबई में आयोजित भाजपा राष्ट्रीय परिषद् में 28 दिसंबर, 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण से संकलित)

भाजपा: भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली पार्टी

शिवप्रकाश

देश में राष्ट्रवाद, गरीब कल्याण, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, पारदर्शिता का आचरण करते हुए कांग्रेस के सम्मुख विकल्प प्रस्तुत करने के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। भारतीय राजनीति के मूर्धन्य विद्वान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने "एकात्म मानववाद" का वैचारिक आधार देकर जिसको पोषित करने का कार्य किया। अपने जन्म से सततवृद्धि की ओर अग्रसर भारतीय जनसंघ लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपातकाल के समय जनता पार्टी में विलीन हो गया।

6 अप्रैल 1980 को मुंबई सागरतट पर अटल गर्जना के साथ 'अंधेरा छंटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा' के संकल्प के साथ भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर नई पार्टी 'भारतीय जनता पार्टी' के नाम से प्रकट हुई। इसका नेतृत्व भारतीय राजनीति के सूर्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज वही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 18 करोड़ सदस्यता वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। देश के अनेक राज्यों में सरकार एवं केंद्र में भारत का नेतृत्व कर रही है। अपने राष्ट्रवादी विचार, गरीब के कल्याण की नीति, प्रखर एवं प्रमाणिक नेतृत्व के कारण भाजपा, देश के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

राजनीति के माध्यम से राष्ट्रवाद की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय एकात्मता को पुष्ट करने का विचार भाजपा ने अपने जन्म काल से रखा। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चयन में लोकतंत्र का पालन करते हुए देश में लोकतंत्र का रक्षण पार्टी का संकल्प बना। समाज में बिना किसी भेदभाव के 'विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पालन करते हुए गरीब उत्थान'ही पार्टी का लक्ष्यबना। बिना किसी भेदभाव अपनी-अपनी पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए देश के विकास में सभी का सहयोग एवं 'देश प्रथम'के सिद्धांत का पालन करते शुद्ध आचरण से देशवासियों की सेवा भाजपा का लक्ष्य बना।

हमारा देश विविधताओं से युक्त है। भाषा, जातियों, पूजा-पद्धति, खानपान, रंग-रूप एवं पहनावा हम सब को एक दूसरे से भिन्न दिखाते हैं। सतही तौर पर विचार करने वाले एवं विदेशी षड्यंत्रों से प्रभावित अनेक लोगों ने इस विविधता के विभेद को ही अपनी राजनीति का आधार बनाया। यह एक राष्ट्र नहीं अपितु जातियों में परस्पर संघर्ष, आदिवासी, शहरवासी, सवर्ण दलित आदि के आधार पर अपनी रोटियां एवं वोट की फसल काटने का प्रयास किया। जबकि भाजपा प्रारंभ से ही यह एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति के सिद्धांत के आधार पर राजनीति करती आई है। विविधता इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि देश का सौंदर्य है। उत्तर पूर्वांचल ने भी भाजपा को चुनाव जिताकर इस स्वर को सुदृढ़ किया है। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि "न तो अब उत्तर पूर्वांचल दिल्ली से दूर है और न ही दिल से दूर है।' बंद, चक्का-जाम, आतंक अब समाप्त होकर वहां विकास की धारा बह रही है। कश्मीर 370 से मुक्त होकर केसर की सुगंध ले रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनूठी पहल "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंतर्गत 'काशी तमिल संगम' ने एकात्मता के विश्वास को गहरा किया है। वेरूवाडी, कच्छ, कश्मीर के लिए संघर्ष करने वाले भाजपा नेतृत्व ने राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकात्मता के भाव को जन-जन में जागृत किया है। इसी कारण देश के कोने-कोने से लेकर दुनिया के सुदूर स्थानों तक लाखों लोग देश भक्ति का समवेत स्वर 'भारत माता की जय' का उद्घोष कर रहे हैं।

देश के राजनीतिक धरातल पर सक्रिय दल अपने अंदर का लोकतंत्र खोते जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया का पालन या तो है नहीं अथवा दिखावा मात्र है। कांग्रेस सहित देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियां परिवारवाद के संकट से ग्रस्त हैं। इस कारण उन दलों का प्रतिभावान नेतृत्व कुंठित होकर दल छोड़ रहा है अथवा निष्क्रिय है। जो दल अपनी पार्टी में लोकतंत्र का पालन नहीं कर सकते, उनसे देश के लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगा कर लोकतंत्र को कुचलने का कार्य किया ही था। परिवारवाद के कारण देश का लोकतंत्र खतरे में आ सकता है, यह आशंका संविधान निर्माताओं के मन में भी थी। भाजपा ने अपने संविधान अनुसार निश्चित अवधि में बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया का पालन करते हुए देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। भाजपा ही एकमात्र ऐसा दल है जिसने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने दल का अस्तित्व समाप्त किया। जबकि अन्य दल चुनाव आयोग, ईवीएम एवं न्यायालय पर प्रश्नचिह्न खड़ा करने का कार्य कर रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान के इस व्यवहार ने भारतीय जनता के मन में भाजपा नेतृत्व के प्रति विश्वास को बढ़ाया है।

गांधीजी अपने आर्थिक चिंतन में देश का विकास स्वदेशी एवं विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर चाहते थे। ग्राम पंचायत चुनना स्वराज का आधार था। पंडित दीनदयाल

उपाध्याय ने सरकारों की सफलता का आधार गरीब कल्याण (अंत्योदय) को माना। स्वदेशी, सादगी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था से हम अपनी आर्थिक उन्नति करें, यह विचार उन्होंने दिया। किसान के खेत को पानी, रोजगार यह उनकी अर्थव्यवस्था के आधार थे। 'उत्पादन में वृद्धि खर्च में संयम' का सिद्धांत उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी` द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नदियों को जोड़ने का प्रकल्प एवं सर्व शिक्षा अभियान, गरीब उत्थान एवं देश के ढांचागत विकास के अनुकरणीय उदाहरण हैं। उसी परंपरा में बहुगुणित वृद्धि करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं, क्रियान्वयन में तकनीकी उपयोग, कृषि सिंचाई योजना एवं आत्मनिर्भरता का मंत्र गांधी जी एवं दीनदयाल जी के कल्पनाओं का साकार रूप है, जिसमें गरीबों का विश्वास अर्जित करते हुए देशतीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।

तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारतीय संस्कृति एवं भारतीय समाज पर आक्रमण ही राजनीतिक दलों की परंपरा बन गई थी। जो जितनी अधिक एवं कठोर गाली देगा वह सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्षवादी हो गया था। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे नेता एवं दल अपने धर्मनिरपेक्षतावाद का आवरण ओढ़ कर देशवासियों को शिक्षा दे रहे थे। जो हिंसा में लिप्त थे, वे धर्मनिरपेक्ष होने का ढोंग रच रहे थे। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भगवान श्रीराम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। धर्मनिरपेक्षता तुष्टीकरण का पर्याय हो गई थी। समाज दुःखी मन से इन दलों के कारनामों को देख रहा था। भाजपा ने कहा हम विकास में कोई पक्षपात न करते हुए सभी को न्याय देंगे। इसी सोच के द्वारा अपनी गरीब कल्याण की योजनायों के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज के विकास का कीर्तिमान भी भाजपा सरकारों ने ही बनाया है। अपने सांस्कृतिक मान बिंदुओं के गौरव के लिए भाजपा ने कदम-से-कदम मिलाकर कार्य किया। आज भारत का सांस्कृतिक गौरव सूर्य के समान चमक रहा है। विश्व में चोरी करके ले जाई गई मूर्तियों को वापस लाने का कार्य हो अथवा श्रीराम मंदिर, काशी का कॉरिडोर, केदारनाथ जी का सौंदर्यीकरण, महाकाल लोक का निर्माण सभी अपनी गौरवगाथा कह रहे हैं।

सन 2014 से पूर्व प्रतिदिन के समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार सुर्खियों में रहता था। राजनेता एवं राजनीतिक दल जैसे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। सरकारी संपत्ति हमारे व्यक्तिगत उपयोग के लिए है जैसे सिद्धांत गढ़े जा रहे थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 'न खाऊंगा ना खाने दूंगा' का उद्घोष कर राजनीति में पारदर्शिता की मिसाल कायम की। 'देश प्रथम' के सिद्धांत का पालन करने वाले अनेक राजनीतिक कार्यकर्ता भाजपा की देन हैं जिन्होंने सत्ता के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर भी अपनी ईमानदारी की छवि को बनाये रखा है। 'राजनीति में सब कुछ जायज है', जहां यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता था, वहीं ईमानदारी से सरकार चलाई एवं पुनः बनाई जा सकती है, यह भाजपा नेतृत्व ने सिद्ध किया है। 2014 से पूर्व में लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ता था, अब भ्रष्टाचारी अपने बचाव में सड़कों पर उतर रहे है, इसके कारण जीवन मूल्य राजनीति में जीवित है, यह विश्वास जनता में जागृत हुआ है।

देश की स्वतंत्रता एवं विकास में सभी का योगदान है, इसके आधार पर सभी महापुरुषों का सम्मान, परमाणु विस्फोट एवं रक्षा क्षेत्र में आधुनिक सेना एवं शत्रु के द्वारा भारत को सम्मानित स्थान विश्व में भाजपा ने दिलाया है। विश्व भर में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित की है। इसका परिणाम है कि केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व भारतीय जनता पार्टी को एवं उसके नेतृत्व को आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। आधुनिकता के साथ, सेवा एवं भारत के विकास का संकल्प ही भाजपा का मंत्र है। इसी आधार पर उसके कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख तक की संरचना कर रहे हैं। भाजपा भारत की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली पार्टी है जो अपने सेवा भाव से भारत के लिए वरदान सिद्ध होगी। ●●●

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठनमंत्री हैं।

44 वें स्थापना दिवस पर कुछ तथ्य

भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल

भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में भी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न वैश्विक अध्ययनों में विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताया गया।

17 वीं लोकसभा में 303 सांसदों के साथ दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार।

सहयोगियों के साथ लोकसभा में 353 सीट।

राज्यसभा में पहली बार भाजपा 100 सीटों तक पहुंची (फिलहाल 93)।

देश में लोकसभा के आधार पर (सहयोगियों के साथ) 45 प्रतिशत वोट।

17 राज्यों में (सहयोगियों के साथ) भाजपा सरकार।

1800 से अधिक विधायक।

राष्ट्रीय सामाजिक समरसता के अग्रदूत डॉ. अंबेडकर

डा. रमन सिंह

आज से लगभग 20 वर्ष पहले सन 2003 जब समाप्ति की ओर था, नियति ने उस सर्दी में एक नया काम सौंप दिया था मुझे। छत्तीसगढ़ महतारी के सेवक, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। इस दायित्व में लगातार 15 वर्ष अपनी यात्रा और भूमिका कैसी रही, इसे इतिहास को तय करना है। लेकिन इस दौरान ईश्वर ने अगर कुछ अच्छे कार्य करा लिए होंगे तो निश्चय ही इसमें जिन महापुरुषों की प्रेरणा रही उनमें बाबा साहब डा. भीम राव आंबेडकर अग्रगण्य हैं। हम सब जिस भी राजनीतिक दायित्व में होते हैं तो स्वाभाविक ही संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ से बंधे होते हैं, ऐसे में अभीष्ट यही है कि हर प्रतिनिधि स्वयं के कार्यों को संविधान निर्माता बाबा साहेब के विचारों की कसौटी पर कसे।

छत्तीसगढ़ के रूप में हमें अपना नया राज्य अटल जी ने दिया। चुनौतियां अपार थीं। आज़ादी के छः दशक गुजर जाने के बाद तक भी हमारा अंचल तब सामान्य मौलिक सुविधाओं से भी वंचित था। अफ़सोस की बात थी हमारे लिए कि सबके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर, शासन अपने लोगों के लिए भोजन तक की गारंटी नहीं दे पाया था। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले सबको भोजन का अधिकार देने से अपनी यात्रा की शुरुआत की और आगे स्वास्थ्य और शिक्षा इन तीन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढे। बाबा साहेब के मूलमंत्र 'शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो', को ही हमने तब अपनी यात्रा का पाथेय बनाया। उनके समानता और समरसता के विचारों पर ही स्वयं को चलना निर्धारित किया, कितना चल पाया, इसे इतिहास पर छोड़ कर बाबा साहेब के जन्मदिन पर उन्हें कुछ शब्दांजलि समर्पित करता हूं।

कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि मध्यप्रदेश-बिहार के आदिवासी अंचल के विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने राज्य विभाजन का प्रस्ताव दिया था, जिसे अटल जी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़-झारखंड बनाकर साकार किया गया। आज वंचितों के लिए हम आरक्षण समेत अन्य प्रावधानों से अपने आदिवासी और वंचित बंधुओं को आगे लाने में सफल हुए तो यह बाबा साहेब के संविधान से ही संभव हुआ है। जिस तरह बाबा साहब आजन्म महिला अधिकारों के लेकर प्रयासरत रहे, स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण देकर एक तरह से हमने बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि ही व्यक्त की थी।

बाबा साहेब के विचारों को जब आप समग्रता में देखेंगे, निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जब उनका मूल्यांकन करेंगे, तो पायेंगे कि वास्तव में राजनीतिक स्वार्थवश उन्हें हमेशा कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया था। एक सोची-समझी रणनीति के तहत उन्हें राष्ट्र के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के तौर पर बताये जाने से बचा गया। उनके परिनिर्वाण के बाद भी जान-बूझ कर उनकी स्मृति को भी हमेशा पूर्वाग्रह का शिकार बना कर प्रस्तुत किया गया। जबकि सच तो यह है कि बाबा साहेब अपनी प्रज्ञा, अपने ज्ञान और कृतित्व से भी अपने समकालीनों से मीलों आगे थे। अगर राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को देखा जाय तो भारतीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान से भरे एक प्रखर राष्ट्रीय के रूप में ही उनका परिचय होगा।

एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, और समाज सुधारक के साथ बाबा साहब प्रखर संस्कृतिवादी भी थे। भारतीयता से ओतप्रोत उनके विचार आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह ही हैं। अखंड भारत के विचार को जीने और उसी के निमित्त अपना जीवन समर्पित करने वाले डा. आंबेडकर ने न केवल प्राण-पण से भारत विभाजन का विरोध किया अपितु वे यह आशा भी रखते थे कि अंततः भारत अखंड होगा। बाबा साहेब ने कहा था – 'मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं। मैं जीवित रहूंगा तो हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो हिंदुस्तान के लिए।' उनके अनुसार, जब तक सामाजिक समरसता का भाव पूर्णतः राष्ट्र में उत्पन्न नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो पाएगी।'' बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले सी.बी खैरमोड़े ने बाबा साहब के शब्दों को उद्धृत करते हुए लिखा है- "मुझमें और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमति है बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाये, और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए।''

यह पंक्तियां लिखते हुए संतोष हो रहा है कि मेरी पार्टी भाजपा को यह शक्ति मिली कि वह जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर सकी। बाबा साहेब भी इस अनुच्छेद के प्रबल विरोधी थे। वे भी अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। न केवल अनुच्छेद 370 बल्कि अन्य राष्ट्रीय सवालों पर भी डा. आंबेडकर के विचारों का आप भाजपा को अकेला उत्तराधिकारी पायेंगे। बाबा साहेब 'एक देश में एक विधान' यानी समान नागरिक आचार संहिता के भी प्रबल पक्षधर थे। उनके मतांतरण को लेकर अनेक बात कही जाती रही है लेकिन वे भारतीयता को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा था 'बौद्धमत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने सावधानी बरती है कि मेरे पंथ-परिवर्तन से इस देश की संस्कृति और इतिहास को कोई हानि न पहुंचे।'

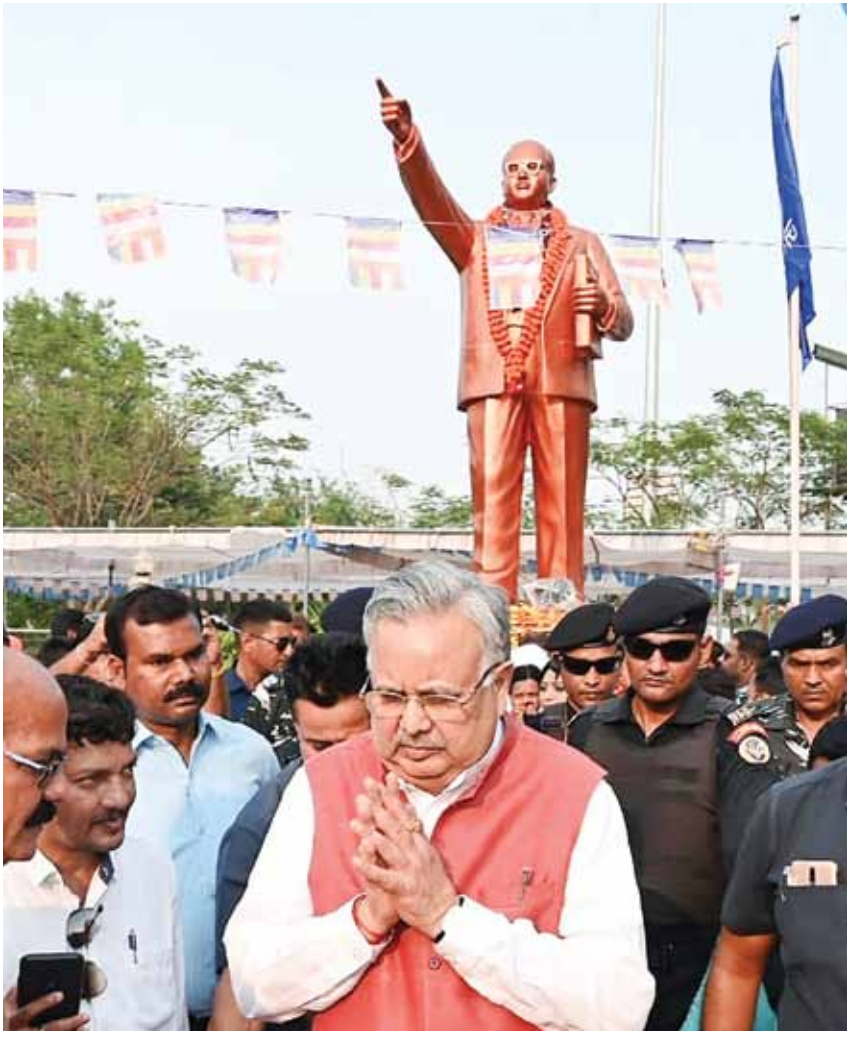

अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपके पास दो मुख्य विकल्प होते हैं। एक तो यह कि उनके विचारों के अनुकूल समाज बनाने के लिए आप स्वयं को समर्पित करें और दूसरा, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें। भाजपा ने इन दोनों अर्थों में बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है। यह जानकर पीड़ा हो सकती है कि 1990 तक बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया गया था। जब भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार सत्ता में आयी तब बाबा साहेब को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। प्रसंगवश यह भी बताया जाना समीचीन होगा कि यही वह समय था जब शासकीय सेवाओं में आरक्षण की भी शुरुआत की गयी। इससे पहले केवल आरक्षण के नाम पर समाज को लड़ाने और वोट बैंक की राजनीति करने का काम ही किया गया था।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा बाबा साहेब के विचारों और उनकी स्मृतियों के संरक्षण के प्रति गंभीर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित बाबा साहेब के घर अलीपुर रोड में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित कराया। मोदी जी की सरकार ने डा. आंबेडकर से जुड़े पांच प्रमुख स्थानों को 'पंच तीर्थ' के रूप में विकसित करने का कार्य किया है। मऊ में उनके जन्मस्थान, लंदन में डा. आंबेडकर मेमोरियल जहां उनकी शिक्षा हुई, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा हुई, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति के रूप उनकी महापरिनिर्वाण भूमि स्थापित किये गए। इसी तरह भाजपा सरकार में ही संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का चित्र लगाया गया। इससे पहले की सरकार वहां जगह नहीं होने का बहाना करती रही थी। ज़ाहिर है इसलिए क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि राष्ट्रीय फलक पर बाबा साहब को स्थान नहीं मिले।

एक बात का ख़ास तौर पर यहां जिक्र किया जाना आवश्यक है कि कांग्रेस हमेशा से इस बात पर अपनी पीठ ठोकती है कि अंतरिम सरकार में उसने बाबा साहेब और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। यहां यह गौर करने वाली बात यह है कि तब कांग्रेस को स्थायी सरकार के लिए जनादेश नहीं मिला था। देश में तो पहला आम चुनाव ही 1952 में हुआ था। यह भी दुखद संयोग ही रहा कि वे दोनों मंत्री (बाबा साहेब और डा. मुखर्जी) अंततः अपमानित होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर ही विवश किये गए थे। उसके बाद पहले आम चुनाव में बाबा साहेब की हार सुनिश्चित करने में कांग्रेस द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गयी थी। यहां तक कि 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा के उपचुनाव में भी सारे प्रयत्न करके बाबा साहेब को लोकसभा पहुचने से रोका गया। अंततः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कोशिशों से बाबा साहेब राज्यसभा पहुंचे। बहरहाल!

बाबा साहेब के जीवन पर जिन तीन गुरुओं का विशेष प्रभाव पड़ा, जिनसे उन्होंने ज्ञान, स्वाभिमान और शील की प्रेरणा ली, वे भगवान बुद्ध, महात्मा कबीर और महात्मा फुले थे। महात्मा कबीर की तरह ही बाबा साहेब ने भी तमाम धर्मों-मतों-सम्प्रदायों की कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। सौभाग्य है कि फिर भी कबीर की तरह ही बाबा साहेब भी लगभग सभी के आदर के पात्र ही रहे। हम सबने उनकी आलोचनाओं के प्रकाश में अपनी कमियों को दूर किया है। कबीर साहब के बारे में कहते हैं उनके दिवंगत होने के बाद उनके पार्थिव देह से कुछ पुष्प निकले जिन्हें सभी मतों ने आपस में बांट लिया। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के कुछ दशक बीत जाने के उपरान्त भी हमारे पास उनके द्वारा अन्वेषित विचार पुष्पों के सुगंध में ही हम सब भी अपने आगे का मार्ग तलाशते रहेंगे।

बाबासाहेब ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में 'कास्ट इन इंडिया' प्रबंध प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा- "भारत में सर्वव्यापी सांस्कृतिक एकता है। यद्यपि समाज अनगिनत जातियों में बंटा है फिर भी वह एक संस्कृति से बंधा हुआ है।" आइये, इसी सुदृढ़ संस्कृति रुपी डोर से बंधे हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हों। तमाम विविधताओं के बावजूद जिस सांस्कृतिक ऐक्य के लिए बाबा साहब समर्पित रहे, हमें उनके ही सपनों का देश बनाने स्वयं को आत्मार्पित करना होगा। बाबा साहेब जिस सामजिक समरसता, देश की एकता, वंचितों का विकास आदि के आजन्म उद्यम किया, वैसा ही भारत, सांस्कृतिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनाना ही बाबा साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ●●●

राहुल गांधी 'देश-विरोधी टूलकिट' का स्थायी हिस्सा

जगत प्रकाश नड्डा

मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भारत विरोधी लोगों को हमेशा से दिक्कत रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश-विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी 'कांग्रेस' भी शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार-बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश-विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं।

देश का अपमान

एक ओर आज भारत जहां प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है, उनके नेतृत्व में जहां जी-20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश की 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। यह देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और यूरोप-अमेरिका को इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की सम्प्रभुता पर हमला है। आखिर यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे राहुल गांधी की क्या मंशा थी? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके क्या वे भारत की आर्थिक घेराबंदी और सामरिक घेराबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं?

स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश के किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान नहीं किया है। राहुल गांधी का यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता में भारी आक्रोश है। जन-प्रतिनिधियों में भी वही आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल को देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी।

विदेशी मदद की मांग दुर्भाग्यपूर्ण

अब यह स्पष्ट हो गया है कि मणिशंकर अय्यर का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाना और सलमान खुर्शीद का मोदीजी को हटाने में विदेशी मदद की मांग करना उनकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व की सोच है। जिस इंग्लैण्ड ने हम पर वर्षों तक शासन किया, उसी सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या है? अब तो मुझे इस पर भी संदेह है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को कितना जानते हैं और कितना समझते हैं? अच्छा होता कि स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को यदि राहुल गांधी सही ढंग से पढ़ते तो उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र की हत्या किसने की और लोकतंत्र की रक्षा किसने की?

कांग्रेस ने की लोकतंत्र की हत्या

राहुल गांधी को आपातकाल का इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस देश में 19 महीनों तक आपातकाल लगाकर लगभग डेढ़ लाख बेगुनाह राजनीतिक कार्यकर्ता, युवा, वृद्ध, महिला... सबको अकारण जेल में डाल दिया गया था। तब बोलने पर प्रतिबंध, लिखने पर प्रतिबंध, मीडिया पर प्रतिबंध, फिल्मों पर प्रतिबंध, गायकों पर प्रतिबंध..... न जाने, किन गुनाहों के लिए किस-किस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। कांग्रेस ने तो देश की सभी संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त किया ही, न्यायपालिका को भी कमजोर करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी थी। राहुल की पार्टी की केंद्र सरकारों ने लगभग 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को बेवजह बर्खास्त किया था। ये होती है लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस द्वारा जिस ढंग से आपातकाल लगाकर देश के संविधान को समाप्त करने का प्रयास किया गया था, उसका प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया और उसके शासन को उखाड़ फेंका। किसी विदेशी ताकत ने नहीं।

राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत को बदनाम करते हैं जबकि आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। इटली की पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को सबसे 'लवेबल पीएम' कहा। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत की विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है।

कार्टून साभारः वन इंडिया हिन्दी

अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी की समझ!

राहुल गांधी कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं बल्कि राज्यों का संघ है। जिसे राष्ट्र के रूप में 'भारत' में विश्वास ही नहीं, उसकी सोच पर क्या कहा जाय? भारत 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' है जिसने पूरी दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा दी। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की देश में कोई सुनता नहीं। देश की जनता उन पर विश्वास करती नहीं। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी का देश से लगभग सफाया हो चुका है।

देश विरोधी टूलकिट गैंग की सक्रियता

जब भी भारत में संसद सत्र शुरू होने वाला होता है, देश विरोधी टूलकिट गैंग अचानक से सक्रिय हो जाता है। कभी पेगासस की झूठी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, कभी आंदोलनों को भड़काया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी किसी विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है। कहा जाता है कि ताली एक हाथ से नही बजती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यहां एक हाथ तो सात समुद्र पार है और दूसरा यहां है और दोनों मिलकर ऐसी ताली बजाते हैं कि अपने देश को भी बदनाम करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। आखिर क्यों भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों चीन और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधियों और कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है?

कांग्रेस व लेफ्ट लिबरल्स की मिलीभगत

विदेशी ताकतें भारत में एक कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सकें। भारत को कमजोर करना Deep State का षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं, पर भारत के करोड़ों-करोड़ देशभक्त नागरिक, कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों के इन मंसूबों को कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। ●●●

भाजपाध्यक्ष की प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित.

सांप्रदायिक तृष्टिकरण का शिकार छत्तीसगढ़

युवा भुनेश्वर साहू की जिहादयों द्वारा नृशंस हत्या

इबादतगाह को बनाया कत्लगाह, रुक नहीं रहा सिलसिला

अनिल पुरोहित

धर्मांतरण को राजनीतिक संरक्षण और तुष्टिकरण ने छत्तीसगढ़ को पिछले साढ़े चार वर्षों में एक ऐसी अंधी गली में लाकर खड़ा कर दिया है कि उससे बाहर झांकने पर देश का सबसे सहिष्णु और शांत कहा जाने वाला यह प्रदेश अब ख़ुद को अराजकता, अशांति, असुरक्षा और अपराधों के चौराहे पर खड़ा पाने के लिए विवश नज़र आ रहा है। कांग्रेस के सत्ता-संरक्षण में फल-फूल रहे इन घातक एजेंडों ने कभी कवर्धा को साम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलसाया तो कभी आदिवासी बहुल बस्तर को हिंसक हमलों से लहूलुहान किया। और अब, उसकी सबसे भयावह परिणति बेमेतरा ज़िले के बिरनपुर ग्राम में हुई है, जहां बहुसंख्यक समाज के युवक भुनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग कर इबादतखाने में महज़ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह उस समुदाय के लव ज़िहाद के एजेंडे का विरोध कर रहा था। इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार सौहार्द्र, भाईचारे की चाहे जितनी जुमलेबाजी कर ले, लेकिन अपनी इस ज़िम्मेदारी से वह पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उसकी नाक के नीचे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री समेत पांच-पांच मंत्रियों वाले संभाग में बहुसंख्यक समाज की धार्मिक आस्थाओं को ठोकरों पर रखकर एक समुदाय चोरी, ऊपर से सीनाज़ोरी कर रहा है, इबादतखाने को क़त्लखाना बना रहा है तो महज़ इसीलिए कि सत्ता के गलियारों से उन्हें ऐसे तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की गारंटी है।

बहुसंख्यक समाज के युवक भुनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग कर इबादतखाने में महज़ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह उस समुदाय के लव ज़िहाद के एजेंडे का विरोध कर रहा था। इस घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

बेमेतरा ज़िले के बिरनपुर गांव में जा कुछ भी हुआ है, उसे किसी भी क़ीमत पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। 08 अप्रैल की दोपहर जिस तरह भुनेश्वर साहू की निर्मम हत्या की गई है, वह दरिंदगी की हद है। इतना ही नहीं, इस दौरान चार पुलिस कर्मी भी घायल हुए। जानकारों की मानें तो यह घटना एकाएक घटित नहीं हुई है। अंतरजातीय विवाह के एक मामले के मद्देनज़र कुछ महीनों से गाँव में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इस विवाद के समाधान के लिए कुछ संगठनों ने पहल की, ज्ञापन आदि सौंपे, लेकिन शासन-प्रशासन की उदासीनता ने इसे अंततः उस मोड़ पर पहुंचा दिया कि दरिंदगी भी थर्रा उठी। बाद में जब तनाव बढ़ा तो प्रशासन हरक़त में आया, परंतु उसने शुरुआत से ही ऐसे क़दम उठाए जो शासन के एजेंडे के मुताबिक़ मुफ़ीद हों। क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अन्य ज़िले से बल बुलवाया और गांव को सन्नाटे की चादर से ढंक दिया। किसी भी बाहरी व्यक्ति को गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि घटना के सच को सामने आने से रोकने की कोशिश शासन-प्रशासन के स्तर पर चल रही थी। यहीं से तुष्टीकरण के एजेंडे की आशंका को भांपकर विश्व हिन्दू परिषद ने इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए 10 अप्रैल को 'छत्तीसगढ़ बंद' का आह्वान किया, जिसे

भारतीय जनता पार्टी समेत उन सभी संगठनों का समर्थन मिला जो बहुसंख्यक समाज की पीड़ा से व्यथित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री अरुण साव पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मृतक के शोकाकुल परिजनों से मिलने और उन्हें ढांढ़स बंधाने बिरनपुर जाने के लिए निकले पर पुलिस ने उन्हें साजा के पास रोक दिया। फलस्वरूप श्री साव वहीं धरने पर बैठ गए। बाद में जब श्री साव पुनः बिरनपुर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें और उनके साथ श्री दीपक ताराचंद साहू, प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा, श्री लाभचंद बाफना, श्री ओमप्रकाश जोशी, श्री नथमल कोठारी, श्री मूलचंद शर्मा, श्री होरीलाल सिन्हा आदि को गिरफ़्तार कर लिया।

इधर, विश्व हिन्दू परिषद ने इस घटना को लेकर प्रदेशभर में राज्य सरकार के रवैए के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया और राज्यपाल को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग के साथ ज्ञापन सौंपने का एलान कर दिया। विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि बिरनपुर में एक मज़हब के 50 से ज़्यादा लोगों ने साजिशन हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके आरोपियों पर कार्रवाई हो। भाजपा ने विहिप के बंद का समर्थन करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में लगातार लव ज़िहाद के आठ मामले हुए हैं और मृत युवक वहां लोगों को जागरूक कर रहा था कि लव ज़िहाद एक अपराध है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने का आरोप जड़ा।

प्रदेश सरकार पर भुनेश्वर साहू की निर्मम हत्या के बाद एकपक्षीय कार्रवाई करने के आरोप भी लगे। भुनेश्वर की हत्या के बाद कई लोगों के नाम से रिपोर्ट दर्ज है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में अब तक सफल क्यों नहीं हो पाई?

छत्तीसगढ़ प्रदेश जब इस भयावह दौर से गुज़र रहा था, प्रदेश सरकार इस संवेदनशील मामले पर मौन साधे बैठी रही। इस मामले में सरकार द्वारा 72 घंटे के बाद मृतक के

परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के ऐलान को नाकाफ़ी बताया गया। ज़िहादी उन्माद के बचाव में कांग्रेस सरकार ने एक हिन्दू युवा की जान की कीमत 10 लाख रुपये आँकी है जबकि समाज ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की थी। ऐसा करके प्रदेश सरकार ने हिन्दू समाज सहित पूरे छत्तीसगढ़िया समाज के ज़ख़्मों पर नमक छिड़का है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तरप्रदेश में 50-50 लाख रुपए बांटे और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे के लिए पूरे प्रदेश के दबाव के बाद मात्र 10 लाख की घोषणा की। प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने क्षोभ व्यक्त कर कहा कि इससे ज्यादा रकम के तो प्रियंका गांधी की गाड़ी से रौंदने के लिए गुलाब के फूल बिछाए गए थे। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि ज़िहादी उन्माद में निर्दोष हिन्दू युवक की नृशंस हत्या हो गई और तुष्टिकरण की हिमायती कांग्रेस और उसकी सरकार के मुख से पीड़ित परिवार के लिए न तो हमदर्दी के दो शब्द निकले और न ही ज़िहादियों के खिलाफ एक शब्द। श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जेहादी उन्माद को भूपेश बघेल सरकार और कांग्रेस कितना भी प्रश्रय दे दे, हिन्दू समाज अपनी क्षमता से इस जेहादी उन्माद और उसके पैरोकारों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा।

इधर, प्रदेश सरकार पर भुनेश्वर साहू की निर्मम हत्या के बाद एकपक्षीय कार्रवाई करने के आरोप भी लगे। भुनेश्वर की हत्या के बाद

कई लोगों के नाम से रिपोर्ट दर्ज है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ने में अब तक सफल क्यों नहीं हो पाई? आख़िर आरोपियों को पकड़ने से प्रदेश सरकार को कौन रोक रहा है? प्रदेश सरकार अपने रवैए से हिंदू समाज के लोगों, ग्रामीणों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है जबकि इस संवेदनशील मामले में सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद रखी जाती है। भाजपा ने फिर राज्य में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद सरकार का यह रवैया फिर से तुष्टिकरण की पुष्टि कर रहा है। प्रदेश सरकार जल्द-से-जल्द भुनेश्वर साहू की हत्या के सभी आरोपियों को पकड़े अन्यथा फिर यह सवाल खड़ा होगा कि आरोपियों को किसका संरक्षण है?

मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान

इस पूरे घटनाक्रम में संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह थी कि मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री अमरजीत भगत ने अपने बयानों से यह प्रमाणित किया कि बहुसंख्यक समाज के प्रति उनका रुख क्या है? एक ओर मुख्यमंत्री बघेल ने लव ज़िहाद को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया, उससे यह धारणा ही पुष्ट हुई कि मुख्यमंत्री अब लव ज़िहाद के बड़े पैरोकार बन गए हैं, जैसा कि प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने कहा। इससे पहले जिहादी उन्मादियों द्वारा की गई हिंदू युवक की हत्या के बाद मृतक की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और प्रदेश के मुख्यमंत्री बघेल ने राजधानी में महापौर के यहां दावत-ए-इफ्तार में शरीक होकर अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया। प्रदेश सरकार के जिस मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में यह घटना हुई, उन्होंने भी इफ्तार की यह दावत उड़ा कर कांग्रेस के हिंदू विरोधी चरित्र का परिचय दिया है। इसी तरह मंत्री अमरजीत भगत का बयान भी बेहद निंदनीय रहा। मंत्री भगत के बयान के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जिहादी आततायियों के समर्थन में प्रदेश का मंत्रिमंडल क्यों सामने आ रहा है? मंत्री भगत द्वारा बिरनपुर के जिहादी उन्माद में निर्दोष युवक भुवनेश्वर साहू की लव जिहाद का विरोध करने पर की गई हत्या को 'बहुत छोटी घटना' बताना प्रदेश सरकार और कांग्रेस की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। जब एक परिवार का चिराग बुझ जाने पर पूरा छत्तीसगढ़ शोकमग्न होकर बंद को स्वतः स्फूर्त सफलता प्रदान कर रहा हो, तब मंत्री भगत का यह बयान शर्मनाक तो है ही, साथ-ही-साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बदनीयती को बेनकाब भी करता है। कांग्रेस सरकार के लोग अपना मूल राजनीतिक चरित्र दिखा रहे हैं।

मंत्री को काफी छोटी लगी यह घटना

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने भी कहा है कि अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ में मंत्री भगत को जिहादियों द्वारा एक हिंदू युवक की हत्या भी 'बहुत छोटी घटना' लगना स्पष्ट करता है कि सत्ता के मद में मंत्री भगत प्रदेश की जनता के प्रति अपने राजधर्म और कर्तव्य को भूल चुके हैं। श्री मरकाम ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण की आग में पूरा बस्तर जल रहा है। नारायणपुर के बाद जगदलपुर में मूल आदिवासियों के साथ मतांतरित लोग हिंसक हमला करते हैं, पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर मारते हैं, तब मंत्री भगत मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं, कवर्धा में दंगाई पवित्र भगवा ध्वज का अपमान करते हैं, तब भी मंत्री भगत खामोश रहते हैं और सरगुजा के महामाया पहाड़ पर रोहिंग्या कब्जा करते हैं, तब भी मंत्री भगत के बोल नहीं फूटते! लेकिन जब बिरनपुर में समाज विशेष के लोग गिरोहबंद होकर बहुसंख्यक वर्ग के घर में घुसकर हमला करते हैं, एक युवक की सरेआम हत्या कर देते हैं, तब मंत्री भगत उसे बहुत छोटी घटना बता रहे हैं। श्री मरकाम ने दो टूक कहा कि मंत्री भगत यह कतई न भूलें कि वे बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं और प्रदेश की जनता इसे भूलेगी नहीं।

जेहादयों पर कार्रवाई के बदले कांग्रेस इसके विरुद्ध उठी आवाज को कुचल रही है

हेट स्पीच की आड़ लेकर प्रदेश सरकार ने इन दिनों अपने विरोधियों पर एफ़आईआर करने का सिलसिला चला रखा है। कवर्धा की घटना के दौरान भी यही सब प्रदेश सरकार ने किया था और निर्दोष लोगों को जेलों में ठूँसने, ज़िलाबदर करने का काम कराया। अब बिरनपुर मामले में भी भाजपा के आठ नेताओं-कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हेट स्पीच के नाम पर नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है। इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने भाजपा ने पैदल मार्च निकाला और 24 घंटे में उन कांग्रेस नेताओं को नोटिस जारी करने की मांग की जिन्होंने कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बदज़ुबानी की, बदसलूकी की। इनमें नंदकुमार बघेल, मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत सहित कई नेताओं की शिकायत भाजपा ने की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक श्री शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री भाजपा प्रवक्ता श्री राजेश मूणत, रायपुर संभाग प्रभारी एवं विधायक श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से पैदल मार्च निकालकर

सिविल लाइन थाने में शिकायत पत्र देकर भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के विरुद्ध हेट स्पीच के लिए नोटिस जारी करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कांग्रेस के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप के तहत नोटिस जारी किए जाने के विरोधस्वरूप सिविल लाइन थाने में कांग्रेस भवन के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने पुलिस को चेतावनी दी है कि जिन कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध शिकायत की है, उन्हें 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी किया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर भाजपा बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शकुंतला साहू, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, जयवर्धन बिस्सा द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों का हवाला देते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की। भाजपा का कहना है कि हेट स्पीच के मामले में पुलिस का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। आखिर हेट स्पीच की परिभाषा क्या है? सत्ताधारी दल के लोग भाजपा नेताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करें तो वह हेट स्पीच के दायरे में नहीं आती, जबकि भाजपा की ओर से कोई भी आपत्तिजनक बयान न देने के बावजूद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हेट स्पीच के बहाने नोटिस जारी की जा रही है। भाजपा ने अपनी शिकायत के साथ बाक़ायदा इन सभी नेताओं के बयान भी संलग्न किए। प्रदेश भाजपा ने पुलिस को सौंपे शिकायत पत्र में सप्रमाण कहा कि नंदकुमार बघेल द्वारा अपने फेसबुक पेज में सदैव हिंदू धर्म की मान्यताओं के विरुद्ध अभद्र वक्तव्य प्रसारित कर समाज के लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है।

जनता की आवाज उठाते रहेंगे : चंदेल

पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि साजा के बिरनपुर में घटित वीभत्स घटना का मुखर होकर उसका विरोध करना प्रमुख विपक्ष दल होने के नाते हमारा अधिकार और नैतिकता, दोनों है और यदि कांग्रेस और पुलिस, दोनों की नजर में यह गैरकानूनी है तो सुन लो तानाशाह मुख्यमंत्री, हम बार बार इस तरह कानून तोड़ेंगे लेकिन प्रताड़ित जनता की आवाज बनने का कार्य हम बार-बार करेंगे। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और लापता गृह मंत्री को चेतावनी दी कि जेल की दीवारें ऊंची कर लो क्योंकि अब इस निर्दयी सरकार के विरोध की आवाजें प्रदेश के कोने-कोने से आएंगीं। ●●●

धूमधाम से मना भाजपा स्थापना दिवस वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हुआ सम्मान

भारतीय जनता पार्टी ने अपना 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर प्रदेश भर में पार्टी के साथ-साथ मोर्चा प्रकोष्ठ की अगुवाई में आगामी पूरे 1 माह तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू की गई। राजधानी रायपुर में सुबह बोरियाकला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में और शाम को रजबंधा मैदान स्थित भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह 9 ध्वजारोहण का कार्यक्रम भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इसके पश्चात परिसर में स्थापित पार्टी के पितृ पुरुषों डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर पार्टी की ओर से श्रद्धा निवेदित की गई। इसके बाद सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन सुना। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान कर पार्टी के विस्तार में उनके अमूल्य योगदान से प्रेरणा लेकर उनका अभिवादन किया गया।

राष्ट्र सेवा और भारत का नाम विश्व में ऊंचा करना भाजपा का उद्देश्यः डॉ रमन

भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के धरातल पर खड़ी

भाजपा देश में कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। जिन सपनों को संजोकर संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक वैचारिक आंदोलन प्रारंभ किया था, उसे प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल जी व जनसंघ भाजपा के मनीषियों ने धरातल पर साकार किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा कर भाजपा अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सार्थक कर रही है। डॉ. सिंह ने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ और पराक्रम की चर्चा करते हुए कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण समर्पण और ध्येय निष्ठा के साथ कार्यकर्ताओं ने जो प्रतिमान गढ़े और भाजपा को सर्व स्वीकार्य राजनीतिक दल का स्वरूप प्रदान किया, उसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता, रजनीश शुक्ला, पूर्व विधायक नंदे साहू, छगन मूंदड़ा, सुभाष तिवारी डॉ. सलीम राज सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी ,संतोष पांडेय,भाजपा मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेश मूणत स्थापना दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने चंडी शीतला मंडल दुर्ग में आयोजित भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उपस्थित पार्टी और आम जनमानस को पार्टी के इतिहास के संबंध में संबोधित किया। वरिष्ठ भाजपा नेता राम विचार नेताम बलरामपुर में स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप बस्तर जिला के भानपुरी मंडल के केसरपाल में बूथ क्रमांक 214 में बूथ कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुए। प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा कवर्धा विधानसभा के बूथ क्रमांक 234 में एवं प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी भाजपा की स्थापना दिवस के अवसर पर रायगढ़ जिला द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक बिल्हा विधानसभा की बिल्हा मंडल में बूथ क्रमांक 214 में, दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी बिल्हा विधानसभा के बिल्हा मंडल के बूथ क्रमांक 173 में, बिलासपुर संभाग प्रभारी किरण देव जगदलपुर विधानसभा के बालीकोंडा शक्ति केंद्र के बूथ क्रमांक 6 में शामिल हुए एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया। रायपुर संभाग प्रभारी विधायक सौरभ सिंह अकलतरा के वार्ड 20 में कार्यकर्ताओं व समाज के वरिष्ठजन के साथ कार्यक्रमों में शामिल हुए, सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव शंकर नगर मंडल में भाजपा की स्थापना दिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। ●●●

ईडी के विरुद्ध दुष्प्रचार

कोर्ट ने 14 विपक्षी पार्टियों की याचिका खारिज

एक याचिका जिसमें 14 विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था, को सुप्रीम कोर्ट ने 05 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ताओं में कांग्रेस के अलावा, द्रमुक, राजद, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आप, राकांपा, शिवसेना (यूबीटी), झामुमो, जद (यू), माकपा, भाकपा, समाजवादी पार्टी और जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल शामिल थे।

याचिका में दावा किया गया था कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से विपक्षी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामलों की संख्या में 'भारी वृद्धि' हुई है।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की और कहा कि अदालतें हमेशा राजनीतिक नेताओं की शिकायतें भी उसी प्रकार सुनती आयी है जैसे वे आम नागरिकों की शिकायतों का संज्ञान लेती हैं। राजनीतिक नेताओं को आम नागरिकों की तुलना में विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं है... एक बार जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि राजनीतिक नेता पूरी तरह से आम नागरिकों के समान हैं, जिनके पास कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 'ट्रिपल टेस्ट' के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

स्टैंड-अप इंडिया योजना

1,80,630 से अधिक खातों में 40,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पांच अप्रैल को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत 7 वर्षों के दौरान 1,80,630 से अधिक खातों में 40,700 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई। उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह मेरे लिए बेहद गर्व और संतोष की बात है कि 1.8 लाख से अधिक महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 40,600 करोड़ रुपये से अधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में स्टैंड अप इंडिया पहल की भूमिका को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि आज हम स्टैंड अप इंडिया की सातवीं वर्षगांठ मना रहे हैं और उस भूमिका को स्वीकार करते हैं जो इस पहल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने और महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने में निभाई है। इसने उद्यम की भावना को भी बढ़ावा दिया है, जिससे हमारे लोग धन्य हैं। एसयूपीआई योजना की सातवीं वर्षगांठ के अवसर पर केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना ने एक ऐसा इको सिस्टम बनाया है जिसने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं से मिलने वाले ऋण के जरिए ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने में एक सहायक वातावरण के निर्माण को सुविधाजनक बनाया है और उसे जारी रखा है। 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है।

9.59 करोड़ लाभार्थी

मंत्रिमंडल से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए नियत सब्सिडी मंजूर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 मार्च को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। पीएमयूवाई के 1 मार्च, 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं।

इस पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल व्यय 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 के लिए 7,680 करोड़ रुपये होगा। सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) 22 मई, 2022 से पहले ही यह सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।

विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों से एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की ऊंची कीमतों से बचाना महत्वपूर्ण है।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को नियत सहयोग कर उन्हें एलपीजी के लगातार उपयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के बीच निरंतर एलपीजी अपनाने और उसका उपयोग सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे पूरी तरह से खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन पर निर्भर हो सकें। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल थी, जो बढ़कर 2021-22 में 3.68 रिफिल हो गई। सभी पीएमयूवाई लाभार्थी नियत सब्सिडी के पात्र हैं।

ग्रामीण और वंचित गरीब परिवारों के खाना पकाने के लिए उपलब्ध तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) को स्वच्छ ईंधन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मई, 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की, ताकि गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।

नल से स्वच्छ पेयजल योजना

देश के 60% ग्रामीण परिवार लाभान्वित

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चार अप्रैल को जारी एक बयान के अनुसार इस समय देश के 60 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। भारत में 1.55 लाख से अधिक गांवों (कुल गांवों की संख्या का 25 प्रतिशत) को अब 'हर घर जल' पहुंच रहा है यानी इन गांवों के प्रत्येक घर के अपने परिसर में नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। चालू वर्ष में जनवरी से मार्च, 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत प्रति सेकंड एक नल कनेक्शन प्रदान किया गया है। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसमें वर्ष 2023 के पहले तीन महीनों के दौरान प्रतिदिन औसत रूप से 86,894 नए नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में (55 एलपीसीडी) पर्याप्त दबाव के साथ निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना है। 'जल जीवन मिशन' की समग्र वित्तीय प्रतिबद्धता 3600 बिलियन (43.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रुपये है, जो इसे विश्व का एक सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम बनाती है। गौरतलब है कि अगस्त, 2019 में 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत के समय 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ (16.65 प्रतिशत) परिवारों के पास ही नल का पानी उपलब्ध था, जबकि इस समय 11.66 करोड़ (60 प्रतिशत) से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में 'नल से जल' की आपूर्ति हो रही है। ●●●

कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने 90 विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे पूर्णकालिक विस्तारक : माथुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर करने संगठन स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्णकालिक विस्तारक प्रशिक्षण शिविर में मार्गदर्शन देते हुए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पूर्णकालिक विस्तारक 1 मई से जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप क्षेत्रों में जाएं और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद ही विश्राम करें। हमें लक्ष्य प्राप्त करना है। संघर्ष के दौरान न थकना है और न रुकना है। यह सरकार दमनकारी है और अनैतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगी लेकिन स्मरण रहे कि भाजपा संघर्ष करती हुई यहां तक पहुंची है। हमने आपातकाल जैसी तानाशाही और प्रताड़ना का मुकाबला किया है और जीत हासिल की है। भूपेश बघेल या कांग्रेस हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। कुछ भी कर लें, भाजपा का कार्यकर्ता डरने या झुकने वाला नहीं है। हम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तीन साल की तानाशाही सरकार को उखाड़ चुके हैं। अब फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को भय मुक्त करने का समय आ गया है। जनता हमारी प्रतीक्षा कर रही है।

उद्घाटन सत्र में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि विस्तारक युद्धवीर हैं। हर बूथ तक पहुंचना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करना है। राज्य सरकार की असफलताओं का ब्यौरा घर घर पहुंचाना है।

राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश जी ने 'वर्तमान समय में भाजपा की सार्थकता तथा समय की मांग' विषय पर केंद्रित मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बूथ मजबूत करने के लिए मार्गदर्शन, समाज के बीच रहने, देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुषों का उदहारण देते हुए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा कैसे अन्य दलों से अलग है।

विस्तारक प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जमवाल ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार एक जैसा हो।आप विस्तारक नियुक्त हुए हैं। ये अत्यंत पुनीत कार्य है। आपने इसको लेकर मानसिकता बनाई है तो ईश्वरीय कार्य है। प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय ने बूथ मैनेजमेंट, बूथ सशक्तीकरण और बूथ विजय अभियान पर विस्तार से चर्चा की।

एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो : गोमती साय

लोकसभा सांसद श्रीमती गोमती साय ने कहा कि आदिवासी संत स्व. गहिरा गुरु के पुत्र, भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, हिन्दू आदिवासी नेता श्री गेंदबिहारी सिंह के साथ बगीचा एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर, आरक्षक राजकुमार मनहर, आरक्षक संतोष उपाध्याय द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो कर, यह कहते हुए कि तुम बहुत नेतागिरी करते हो, दुर्गापारा से मारपीट कर पुलिस वालों के साथ बल प्रयोग कर थाना ले आया, जो कि बहुत ही निंदनीय एवं आपत्तिजनक घटना है जिससे मैं व्यथित हूँ। कांग्रेस ने इस हद तक अपनी पुलिस को छूट दे रखी है कि वे किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करें। खासकर हिन्दू नेता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार का प्रहार कर रही है।

श्रीमती साय ने कहा कि मैं, बगीचा एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर, आरक्षक राजकुमार मनहर, आरक्षक संतोष उपाध्याय के खिलाफ अपराध दर्ज कर एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग करती हूँ। सरकार और पुलिस प्रशासन अपराध दर्ज कर कार्रवाई नहीं करती है। तो सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे।

कांग्रेस की दलित नेत्री को न्याय दिलाएं प्रियंका : सरोज

राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस महामंत्री प्रियंका वाड्रा से पूछा कि 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का नारा देने वाली प्रियंका गांधी अपनी ही पार्टी की नेत्री और कांग्रेस उम्मीदवार रहीं दलित लड़की अर्चना गौतम की लड़ाई में क्यों साथ नहीं दे रही हैं? अर्चना गौतम के पिता ने बाकायदा एफआईआर करके अपनी बेटी के साथ प्रियंका गांधी के सचिव संदीप कुमार द्वारा किये गए दुर्व्यवहार, जातिसूचक गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कराया है।

यह घटना रायपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान हुई थी। अपनी ही पार्टी की नेत्री के खिलाफ अपने नजदीकी सचिव द्वारा किये इस दुर्व्यवहार पर, दलित महिला के साथ हुए अन्याय पर प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं? क्या उनकी सहमति से उनके सचिव ने यह अपराध किया है? क्या प्रियंका जी को अपनी नेत्री जो दलित महिला हैं, पर भरोसा नहीं है?

सुश्री पांडे ने पूछा कि क्या दलित महिला अर्चना गौतम को न्याय दिला कर प्रियंका जी महिलाओं का भरोसा बहाल करेंगी?

मोर आवास- मोर अधिकार अभियान ने राजनीतिक मौसम बदल दिया

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाजपा ने इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत की रणनीति पर मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण साव ने अपने सम्बोधन में कहा कि मोर आवास मोर अधिकार अभियान की सफलता ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक मौसम बदल दिया है। इस अभियान को प्रदेश भर में हर विधानसभा क्षेत्र में मिले प्रबल जन समर्थन से भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस की भ्रष्ट, नाकारा, जनविरोधी, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी, तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक संघर्ष करने तैयार है। मोर आवास- मोर अधिकार अभियान को मिले अभूतपूर्व जन समर्थन से कांग्रेस और उसकी सरकार की नींद उड़ गई है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जीत का रास्ता बना लिया है और अब हम सभी कार्यकर्ताओं को जनता के साथ लक्ष्य हासिल करने सुविचारित रूप से आगे बढ़ना है।

जनता के बीच जाएंगे भाजपा के सभी मोर्चा पदाधिकारी : नितिन नबीन

भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी श्री नितिन नबीन ने सभी मोर्चों के प्रभारियों, अध्यक्षों व महामंत्रियों की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सभी मोर्चा अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न वर्गों के बीच जाएंगे। किसान मोर्चा किसानों को बतायेगा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए क्या क्या योजनाएं दी हैं। मोदी जी किसानों की बेहतरी के फैसले करते हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाकर बेरोजगारी भत्ता इत्यादि विषयो पर भूपेश बघेल सरकार की धोखेबाजी को तथ्यों के साथ बतायेगा। अनुसूचित जनजाति मोर्चा तेंदूपत्ता के मुद्दे पर वनवासियों के बीच होगा। महिला मोर्चा शराबबंदी, स्वयंसहायता समूह से किये धोखाधड़ी के मामलों में महिलाओं के साथ है और महिलाओं के हक में संघर्ष कर रहा है। महिला मोर्चा अपने कार्यक्षेत्र के विषयों पर महिलाओं के बीच जाएगा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा सहित सभी मोर्चा जनता के बीच जाएंगे।

प्रभारियों का शक्तिकेन्द्रों में प्रवास बूथ मजबूती की शुरूआत का पहला कदम : सरोज पाण्डेय

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बूथ सशक्तिकरण महाभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में बूथ की मजबूती के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण में बूथ इकाई की मजबूती हेतु पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मंडलों के बूथों में घर घर जनसंपर्क किया और 31 सदस्यीय प्रभावी मतदाताओं की सूची का निर्माण किया फिर इसकी फिजिकल के साथ साथ डिजिटल एंट्री करवाई गई। इसी कड़ी में भाजपा द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान की विधानसभा वार पृथक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। पश्चिम विधानसभा की बैठक के पश्चात रायपुर उत्तर विधानसभा की बैठक का आयोजन जिला कार्यालय एकात्म परिसर में किया गया। बूथ सशक्तिकरण रायपुर उत्तर की विधानसभा समीक्षा बैठक रायपुर शहर जिला अध्यक्ष जयंती भाई पटेल के नेतृत्व में जिला कार्यालय एकात्म परिसर में आहूत की गई। मुख्य रूप से बैठक में समीक्षा हेतु राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय उपस्थित रही।

छत्तीसगढ़ को चाहिए डबल इंजन की सरकार : साव

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की सरकार की जरूरत है। वर्ष 2018 तक जब तक डबल इंजन की सरकार यानी केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार रही, तब तक छत्तीसगढ़ का विकास हुआ और छत्तीसगढ़ की जनता को इसका लाभ मिला। लेकिन जब से भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ का विकास रुक गया है और यह सरकार जनता और केंद्र सरकार के बीच बाधक बन कर छत्तीसगढ़ की जनता के हितों पर प्रहार कर रही है। सभी ने देखा है कि किस तरह 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित होना पड़ा। चावल घोटाला करके गरीब का अन्न खा गए, किस तरह गरीब के घर नल नहीं लगने दिया जा रहा। वहीं, दूसरी ओर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि जब झीरम कांड हुआ था, तब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और कहते थे कि झीरम के सबूत उनकी जेब में हैं। साढ़े 4 साल हो गए। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने यह सबूत अपनी जेब से नहीं निकाले। वे बताएं झीरम के सबूत अपनी जेब से क्यों नहीं निकालते?

महार/महरा/मेहर जाति को अजा में शामिल करने का आग्रह

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखकर 1992 से आरक्षण से वंचित छत्तीसगढ़ के महार/मेहरा/मेहर जाति को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति की सूची में प्रतिस्थापित करने का आग्रह किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में महारा/महरा जाति को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति की सूची के सरल कमांक 33 में महार/मेहरा/मेहर के साथ प्रतिस्थापित करने हेतु समाज के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। उन्होंने विशेष ध्यान देते हुए उल्लेखित किया कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में महारा समुदाय की जनसंख्या लगभग 6 लाख से अधिक है, जो वर्ष 1992 से आरक्षण से वंचित हैं। इस संबंध में डॉ रमन सिंह ने गृह मंत्री श्री शाह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 (2) के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव संसद के विचारार्थ एवं पारित करने हेतु विधेयक के रूप में प्रसंस्कृत किये जाने के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देने का आग्रह किया।

गैर जिम्मेदार संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दें : केदार कश्यप

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने आरक्षण विधेयक जैसे गंभीर विषय की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जिस प्रकार से राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ आरक्षण संशोधन विधेयक लौटाए जाने का उल्लेख करते हुए टिप्पणियां की हैं और बिना इसकी पुष्टि किए प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा बाद में यह स्पष्ट हो जाने पर कि राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक वापस नहीं लौटाया है, उनका यह कहना कि मीडिया की खबरों के आधार पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, उन्हें जानकारी नहीं है, यह मंत्री के रूप में उनका बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। क्या छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार मीडिया की खबरों पर चल रही है? क्या संसदीय कार्य मंत्री को इतने संवेदनशील विषय में जानकारी नहीं होना चाहिए? आखिर संसदीय कार्य मंत्री कर क्या रहे हैं? राज्य के संसदीय कार्य मंत्री को अपने विषय से जुड़ी जानकारी न होना साबित कर रहा है कि यह सरकार हवा में तैर रही है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बिना किसी तथ्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन, भाजपा और केंद्र सरकार के विरुद्ध अनर्गल प्रलाप करने की जो परंपरा अपना रखी है, उसी का अनुसरण उनके मंत्री कर रहे हैं। राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक सरकार को वापस नहीं लौटाया और संसदीय कार्य मंत्री ने बिना किसी पड़ताल के बयानबाजी करते हुए मंत्री की मर्यादा भंग कर दी। संसदीय इतिहास में ऐसा अजूबा पहली बार सामने आया है। ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम की पटकथा कांग्रेस के दफ्तर में लिखी गई है।

हत्यारें हाथ काट कर ले जा रहे, पुलिस का कोई पता नहीं : कौशिक

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बिलासपुर में हुई युवक की हत्या को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश की पुलिस आज जितनी बेबस लाचार है उतनी कभी नहीं रही वजह कांग्रेस की लापरवाही है हत्या, चोरी, बलात्कार, तस्करी और नशाखोरी इस मात्रा में बड़ी हुई है कि आम लोगों का अब जीना दूभर हो गया है। अपराधी दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या करके हाथ काट कर ले जातें हैं और पुलिस का कोई अता-पता नहीं है।

श्री कौशिक ने कहा गांव गांव के साथ राजधानी व न्यायधानी की पुलिस को सख्त होना चाहिए, अपराधियों पर नकेल कसनी चाहिए। इसके विपरीत अपराधियों को देखकर पुलिस के कदम पीछे हो रहे है। उन्होनें कहा कि यह केवल अकेली घटना नहीं है पिछले साढ़े चार वर्षो में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो शासन व प्रशासन के लापरवाही व कुनीतियों का प्रमाण है।

श्री कौशिक ने कहा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश की सरकार व पुलिस कर क्या रही है? दिनदहाड़े इस तरह की हत्याएं निरंतर हो रही है और पुलिस को इसकी जानकारी ही नहीं मिल पा रही है यह समझ से परे है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस तरह से चिंता मुक्त है मानो जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदारी ही नहीं है। रही बात पुलिस प्रशासन की तो पुलिस केवल राजनीतिक मामलों में कांग्रेस सरकार को खुश करने के लिए अपनी सक्रियता दिखा रही है।

आम लोगों के लिए घट रही घटनाएं उनके लिए आम हो गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और बढ़ते अपराध पर अंकुश लागाने में विफल कांग्रेस सरकार केवल खानापूर्ति के लिए कार्रवाई करती है। अगर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करती तो इस तरह की वारदातें नहीं होती।

प्रदेश को खुशहाल बनाना है तो बुलडोजर भी चलाना होगा, तुष्टिकरण की राजनीति भी बंद करनी होगी : बृजमोहन

वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बयान कि "बुलडोजर वाले अब नहीं चलेंगे" पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में और देश में खुशहाली लाना है तो हमको बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा और तुष्टिकरण की राजनीति भी बंद करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ जो बदहाली के दौर से गुजर रहा है उसके पीछे कांग्रेस की यही नीति है जिसका परिणाम पूरा प्रदेश भुगत रहा है। बृजमोहन ने कहा कि छत्तीसगढ़ आबादी के दृष्टिकोण से देश का 22वें नंबर का राज्य है। परंतु अपराध में यह टॉप 10पर है। छत्तीसगढ़ आज ऐसा राज्य बन गया है जहां हर तरह के अपराधी, असामाजिक कृत्य हो रहे हैं। गली-गली में शराब बिक रही है, सड़कों पर रोजाना चाकूबाजी हो रही रहे हैं, रेत माफिया, जमीन माफिया, कोल माफिया, ड्रग माफिया सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। हमारी भाजपा सरकार आने पर निश्चित रूप से हम ऐसे अवैध काम करने वालों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाएंगे। उन्होंने कहा कि यहां पर लगभग 10 हजार पुलिस के पद रिक्त है। जिसके चलते विभिन्न अपराध के मामलों में जांच तो प्रभावित हो ही रहा है, कानून व्यवस्था भी बदतर हो रही है।

कांग्रेस नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने भाजपा ने निकाला पैदल मार्च

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधायक शिवरतन शर्मा,पूर्व मंत्री भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत, रायपुर संभाग प्रभारी एवं विधायक सौरभ सिंह के नेतृत्व में आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर से पैदल मार्च निकालकर सिविल लाइन थाने में शिकायत पत्र देकर भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों के विरुद्ध हेट स्पीच के लिए नोटिस जारी करने की मांग की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कांग्रेस के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप के तहत नोटिस जारी किए जाने के विरोध स्वरूप सिविल लाइन थाने में कांग्रेस भवन के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पुलिस को चेतावनी दी है कि जिन कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध शिकायत की है, उन्हें 24 घंटे के अंदर नोटिस जारी किया जाए। ऐसा नहीं किए जाने पर भाजपा बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, मंत्री अमरजीत भगत, मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शकुंतला साहू, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, धनंजय सिंह ठाकुर, जयवर्धन बिस्सा द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयानों का हवाला देते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग की।

प्रदेश के कथित विकास को मुख्यमंत्री स्वयं ढूंढने निकले हैं : कौशिक

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के विकास में पूरी तरह से बाधक साबित हुई है। उन्होनें कहा कि मूलभूत सुविधा पाना जनता का हक है मगर कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की सभी जनता मूलभूत सुविधाओं के लिये भी तरस रही है अब तो प्रदेश के कथित विकास को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं ढूंढ़ रहे हैं। श्री कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के पास जब कार्य करने का समय था तब तो कुछ किया नहीं अब चुनावी वर्ष पर जनता के दिखाने के लिये मुख्यमंत्री विधानसभा दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में आज कोई वर्ग खुश नहीं है आज प्रदेश का हर वर्ग युवा, महिला एवं किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि गांवों में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आज भी मरीजों को खाट पर ढोने विवश है, पूरे प्रदेश को खोदापुर में तब्दील करने वाली इस भ्रष्ट भूपेश सरकार से आम जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है। श्री कौशिक ने कहा कि पूरे प्रदेश की सड़कें उखड़ गई है और प्रदेश की सरकार उन्हें बनाने की स्थिति में नहीं है। सभी जगह अखबारों में लगातार खबरें आ रहीं है कहीं किसी गर्भवती महिला को खाट पर अस्पताल ले जाया जाता है तो कहीं किसी बीमार व्यक्ति की एंबुलेंस नहीं पहुंच पाने से मौके पर मौत हो जाती है उन्होनें कहा कि आज पूरा प्रदेश पानी की समस्या से जुझ रहा है।

कांग्रेस संगठन के बीच बदलाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता का तंज

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं और प्रदेश सरकार में कोहराम की गूंज सुनाई पड़ रही है। श्री गुप्ता ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चल रही सियासी कवायद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह उठापटक इस बात की तस्दीक करती है कि कांग्रेस के अंदरखाने सत्ता और संगठन में तालमेल का अभाव है। चुनावी वर्ष में कांग्रेस में इस ऊहापोह की परिणिति किस रूप में होगी?

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। कई दिनों से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की ख़बरें सियासी पारे को गर्म कर रही हैं। लेकिन, प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की घोषणा हाईकमान नहीं कर पा रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाईकमान के अनिर्णय की स्थिति की वजह यह है कि जो बदले जाने हैं, उनका एक गुट है जो संगठन पर दबाव डाल रहा है, इधर नए संभावित प्रदेश अध्यक्ष का भी अपना एक गुट है। इसलिए बार-बार यह खबरें आती है कि 'वो' आने वाले हैं और 'ये' जाने वाले हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसी दशा में 'जाने वाले' और 'आने वाले' के बीच में जो यह लड़ाई चल रही है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पूरी तरह बिख़र चुकी है, अंदर से टूट चुकी है। श्री गुप्ता ने कहा कि आपसी तालमेल जैसी कोई बात इनमें रह नहीं गई है। इसके चलते सत्ता और संगठन में भी समन्वय का पूरी तरह अभाव हो गया है। श्री गुप्ता ने कहा कि ऐसे हालात में उस पार्टी का क्या होना है, जहां मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को ही बार-बार अपमानित किया जाता है। ●●●

डिजिटल क्रांति से बदलता भारत

ओ. पी. चौधरी

भारत के संदर्भों में 8 वर्ष पहले जब डिजिटल इंडिया की बात की जाती थी, तो या तो मजाक उड़ाया जाता था या समस्याएं गिनाई जाती थी या फिर अव्यावहारिक कह दिया जाता था। लेकिन आज महज इन कुछ सालों में देश में हुआ बदलाव सबको चकित कर देने वाला है। आज कोई ठेलावाले हों या पान दुकान वाले, रिक्शा चालक हों या सब्जी बेचने वाले; सभी के हाथ में स्मार्ट फोन है और सभी अपना लेनदेन डिजिटल माध्यम से सहजता के साथ कर रहे हैं। औपचारिक शिक्षा की तमाम सीमाओं और डिजिटल डिवाइड की बड़ी बहस के बीच भारतीय जनमानस के इन सभी वर्गों ने अपने टेक-सेवी होने का प्रमाण देकर दुनिया को चौंका दिया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को 'डिजिटल इंडिया' अभियान की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक ओर सरकारी विभागों और देश की जनता के बीच तकनीक आधारित, पेपर लेस संबंध स्थापित करना था, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में आम लोगों और निजी क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन का सूत्रपात करना भी था। डिजिटल इंडिया के तीन मुख्य घटक हैं: डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और जन सामान्य के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।

मोदी जी का विजन बदलते विश्व में भारत को आगे बढ़ाने के लिये आधुनिक तकनीकों की अनिवार्यता के संबंध में सुस्पष्ट है। वे स्वयं भी नयी तकनीकों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के पूर्व 2013-14 में ही उन्होंने वर्चुअल रैली, सोशल मीडिया और होलोग्राम जैसी नयी तकनीकों का भरपूर उपयोग करके अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया था, जो उस समय बिल्कुल असामान्य बात थी। अपने तकनीकी उन्मुख विजन के अनुसार उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुये और प्रधानमंत्री बनने के बाद डिजिटल माध्यमों को देशहित में प्रयोग करने के लिए योजनाबद्ध और क्रांतिकारी तरीके से काम किया।

"डिजिटल इंडिया" मिशन का सूत्र वाक्य 'पावर टू इमपावर' है। तकनीक स्वयं में एक पावर तो है,लेकिन उसका प्रयोग आम लोगों को इमपावर करने में करना, किसी भी नीति निर्माता के विजन पर निर्भर करता है। सिस्टम और सुविधाओं के बीच गैप खत्म करना समय की मांग है। डिजिटल इंडिया ने यह कैसे संभव किया है, इसका शानदार उदाहरण 'डिजीलॉकर'

है। सभी पहचान पत्र एवं अन्य जरूरी दस्तावेज इसमें सुरक्षित रहते हैं। कोविड महामारी के समय कई शहरों के शैक्षणिक संस्थाओं में इसी की मदद से वेरिफिकेशन किया गया। बिजली-पानी का बिल भरना हो या इनकम टैक्स का भुगतान, डिजिटल इंडिया के माध्यम से सब काफी आसान और तेज हो गया है। गरीबों को राशन देने के लिये अब एक ही कार्ड पूरे देश में मान्य हो रहा है। 'स्वामित्व योजना' से जमीनों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जब सभी शिक्षण संस्थान बंद पड़े थे, तब घर बैठे बच्चे डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही अपनी पढ़ाई को जारी रख पाये। आज भी ऑनलाइन क्लास महानगरों और गांव-कस्बों के बीच के भेद को समाप्त कर रहा है। कोविड के दौरान दुनिया के सबसे बड़े कांटेक्ट ट्रेसिंग स्वदेशी एप 'आरोग्य सेतु' से 22 करोड़ लोग जुड़े और संक्रमण को रोकने में बड़ी मदद मिली। CoWin ऐप में 110 करोड़ लोग जुड़कर अपने टीके का रजिस्ट्रेशन कराके ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे हैं। आज सरकार ने GeM:गवर्नमेंट-इ-मार्केटप्लेस पोर्टल के जरिये सरकारी खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। इसमें 50 लाख से अधिक आपूर्तिकर्ताओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट पोर्टल आईआरसीटीसी पर प्रति दिन लगभग 15 लाख लोग ऑनलाइन टिकट बुक करा रहे हैं, इससे पारदर्शिता बढ़ी है और रेलवे टिकटों के गड़बड़झाले पर लगाम लगा है। डिजिटल क्रांति का ही परिणाम है कि आज भारत का आम नागरिक घर बैठे शेयर मार्केट में हिस्सा ले रहा है और भारत के शेयर मार्केट में घरेलू रिटेलर एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई रकम भी डीबीटी के जरिये सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है। पिछले 4 सालों के आंकड़ों को देखें तो कुल 2258 करोड़ बार हितग्राहियों के खाते में कुल 20 लाख 77 हजार करोड़ रुपए भेजे गये। कभी देश के तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा ही लाभार्थी तक पहुंचता है। आज देश में डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि मोदी जी 1 रुपया किसी हितग्राही के खाते में भेजते हैं तो हितग्राही को पूरा 1 रुपया मिल जाता है। यह केवल डिजिटल इंडिया और JAM:जनधन आधार और मोबाइल के मर्जिंग की रणनीति से ही संभव हो सका है।

पूरी दुनिया का 40 प्रतिशत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट आज अकेले भारत में हो रहा है। भारत,चीन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़कर आज पहले नम्बर पर पहुंच चुका है।

पूरी दुनिया का 40 प्रतिशत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट आज अकेले भारत में ही हो रहा है। भारत, चीन और अमेरिका जैसे देशों को पीछे छोड़कर आज पहले नम्बर पर पहुंच चुका है। भारत सरकार द्वारा यूपीआई की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। हाल ही में विश्व की प्रसिद्ध टेक कंपनी गूगल ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड को डिजिटल पेमेंट के लिये भारत के यूपीआई जैसे प्लेट फार्म के उपयोग की सलाह दी। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2014-15 में डिजिटल ट्रांजेक्शन की संख्या 440 करोड़ थी,जो बढ़कर साल 2021-22 में 7228 करोड़ हो गई। अगर राशि की बात करें तो यह आंकड़ा जहां साल 2014-15 में 76.1 लाख करोड़ रूपये थी,जो लगातार बढ़ते हुए साल 2021-22 में 234.6 लाख करोड़ रूपये हो गया।

ये सब बड़े परिवर्तन आखिर संभव कैसे हुये? इस परिवर्तन के पीछे एक बड़ी सोच के साथ की गयी मोबाइल और इंटरनेट की क्रांति है। आज भारत में 45 करोड़ से अधिक स्मार्ट फोन उपयोगकर्त्ता हैं, यह संख्या 2030 तक 100 करोड़ को पार कर जाने का अनुमान है। देश में 2014 में महज 18 करोड़ 80 लाख इंटरनेट उपयोगकर्त्ता थे, यह संख्या 2021 में 83 करोड़ पहुंच गयी और 2025 तक यह संख्या 90 करोड़ को पार कर जायेगी। 2014 में हमारे देश में महज 2 मोबाइल उत्पादक कंपनियां हुआ करती थीं, आज 200 से अधिक कंपनियों के साथ हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल उत्पादक देश बन गये हैं। इसके पीछे सरकार की पीएलआई स्कीम,मेक इन इंडिया,मेक फार वर्ल्ड की रणनीतियों का योगदान है।

डिजिटल इंडिया मिशन में कई चुनौतियों को भी ध्यान रखना होगा। पूरे देश भर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, विशेषकर जम्मू कश्मीर, नार्थ ईस्ट, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, दुरूह गांवों तक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाना। दूसरा, डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना और तीसरा साइबर क्राइम की उभरती चुनौतियों से निपटना। भारत सरकार इन चुनौतियों के मद्देनजर भी सजगता से कार्य कर रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी के बयान में प्रस्तुत एक आकलन के अनुसार भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था 2020 में 85-90 अरब अमेरिकी डॉलर तक थी और इसके 2030 तक बढ़कर 800 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। हम कह सकते हैं कि इस मिशन की भावी संभावनाएं असीम हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि का ही परिणाम है कि आज डिजिटल इंडिया देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। डिजिटल पावर से लोगों को इमपावर करके इस मिशन के सूत्र वाक्य "पावर टू इमपावर" को वास्तविक अर्थों में चरितार्थ किया गया है। साथ ही हमें डिजिटल डिवाइड के खतरों से भी देश को बचाना है, ताकि समावेशी विकास को वास्तविक अर्थों में चरितार्थ किया जा सके। ●●●

लेखक पूर्व आईएएस और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं.

निवेदन

दीप कमल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं। फोन से भी जानकारी दे सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में संगठन से संबंधित कोई गतिविधि या पत्रिका में प्रकाशन योग्य कोई समाचार हो, तो उसे भी निम्नलिखित माध्यमों से भेजने का आग्रह है।

कार्यकारी संपादक, दीप कमल, प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर
डूमरतराई, रायपुर। (छग), फोन : 0771-2233500, WhatsApp : 9425507006, Email : jay7feb@gmail.com

दीवार पर लिखी ईबारत **अब की बार भाजपा सरकार**

RNI No.CHHHIN/2004/13926

बिहू पर असम ने रचा इतिहास

दुनिया के सबसे बड़े बिहू समारोह में 11000 से अधिक कलाकारों ने लिया हिस्सा

दीपकमल के पिछले सभी अंक पढ़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।